'ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य): एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (बालोद जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सपना शर्मा सॉरस्वत[a], लक्ष्मण कुमार महिलकर[b]

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, (छ.ग.), भारत.

(Corresponding Author) सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, (छ.ग.) भारत.

सारांश प्रस्तुत शोध पत्र 'ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य): एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (बालोद जिले के विशेष संदर्भ में) से संबंधित है। ग्राम पंचायत 29 विषयों पर प्रकार्य कराने के लिए जवाबदेही है, जिसमें समस्त ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम विकास हेतु कर्तव्य संपादन के साथ अधिकार प्रदान किया गया है। व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी मिलने पर ग्राम पंचायत संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए सूचित करता है, जिस पर तत्काल पहल होता है। उक्त व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम विकास हेतु भागीदार बनाया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययनगत क्षेत्र के विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य) की स्थिति एवं योगदान को ज्ञात किया गया है।

प्रस्तावना:—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 द्वारा ग्रामवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को 29 विषयों पर कार्य कराने का अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान किया गया है, जोकि इस अधिनियम की धारा 49 में ग्राम पंचायत के प्रकार्य तथा धारा 54 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ और सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत की शक्तियाँ वर्णित है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत निधि में उपलब्ध धन राशि से ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों के भीतर, कार्य कर सकेंगे:—

अध्ययन के उद्देश्य:—ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य) को ज्ञात किया गया है।

अध्ययन की उपकल्पना:—ग्राम विकास में प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व (सरपंच) की तुलना में ग्रामीण नेतृत्व (पंच) की भूमिका कम होते हैं।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त शोध पद्धति

(अ) उत्तरदाताओं का चयन:—प्रस्तुत अध्ययन हेतु 2009—2010 के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बालोद जिले के ग्राम पंचायत के निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व उत्तरदाता है, तथा अध्ययन के लिए दो स्तरों में निदर्श चयन किया गया है जिसमें प्रथम प्रत्येक तहसील के कुल ग्राम पंचायत का 5% अर्थात् 21 ग्राम पंचायत का चयन तथा द्वितीय चयनित ग्राम पंचायत से कुल 326 उत्तरदाताओं का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। जिसमें अधिकांश सरपंच एवं उपसरपंच का चयन किया गया है। इस प्रकार बालोद जिले के कुल निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि 6519 का 5%, 326 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है, तथा दो स्तरों के निदर्श चयन में लाटरी पद्धति का उपयोग किया गया है।

(ब) तथ्य संकलन की प्रविधियॉं, उपकरण एवं विश्लेषण:—प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची उपकरण के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है, संकलित तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण, सारणीयन करने के पश्चात् उनका विश्लेशण सांख्यिकी एवं तार्किक दोनों आधार पर किया गया है। तथा सांख्यिकी विश्लेषण में कार्ल पियसर्न द्वारा प्रतिपादित काई वर्ग परीक्षण सह—संबंध गुणांक का उपयोग किया गया। प्रत्येक निष्कर्ष को प्राप्त तथ्यों के तार्तिक विश्लेषण के माध्यम से निर्मित किया गया है।

ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका

ग्रामीण नेतृत्व की प्रत्येक भूमिका को कुल चयनित सरपंच उत्तरदाता 20 में से, उपसरपंच उत्तरदाता 16 में से, पंच उत्तरदाता 290 में से ज्ञात कर प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व, उप प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व तथा अन्य ग्रामीण नेतृत्व की भूमिकाओं का विश्लेषण किया गया है।

a. *Corresponding Author: drsapanasharma@gmail.com • 9893467679

तालिका क्रमांक 1

पेयजल व्यवस्था में उत्तरदाताओं की भूमिका

क्र.	पेयजल व्यवस्था में उत्तरदाताओं की भूमिका	उत्तरदाताओं के पद			आवृत्ति (%)
		सरपंच आवृत्ति (%)	उप सरपंच आवृत्ति (%)	पंच आवृत्ति (%)	
1.	पानी टंकी का निर्माण	17 (85)	09 (56.26)	120 (41.37)	146 (44.79)
2.	पेयजल स्रोत पर उचित दवाई का छिड़काव कराना	18 (90)	12 (75.00)	220 (75.86)	250 (76.69)
3.	घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण	19 (95)	16 (100)	235 (81.03)	270(82.82)

उपरोक्त तालिका में पेयजल व्यवस्था के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका से यह ज्ञात हुआ कि, पानी टंकी का निर्माण कराने में 44.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेयजल स्रोत पर उचित दवाई का छिड़काव कराने में 76.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण कराने में 52.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

पेयजल व्यवस्था क्षेत्र के कार्यों पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका के विश्लेषण से स्पष्ट है, कि ग्रामीणों के प्रतिदिन के आवश्यक कार्यो पर ग्रामीण नेतृत्व का योगदान अपेक्षाकृत सामान्य है, अतः ग्रामीण नेतृत्व में ग्राम विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने की आवश्यकता है।

तालिका क्रमांक 1.1

उत्तरदाताओं की आय का पानी टंकी निर्माण की भूमिका के मध्य सह–संबंध

क्र.	मासिक आय (रू. में)	पानी टंकी निर्माण		योग आवृत्ति (%)
		हाँ (%)	नहीं (%)	
1.	2000 से कम	017 (16.84)	084 (83.16)	101 (30.97)
2.	2001–4000	086 (56.22)	067 (43.78)	153 (46.93)
3.	4001–6000	019 (63.34)	011 (36.66)	030 (09.20)
4.	6001 से अधिक	024 (57.15)	018 (42.85)	042 (12.90)
	महायोग	146 (44.79)	180 (55.51)	326 (100)

काई वर्ग का परिकलित मान = 44.496

सार्थकता स्तर p=0.05

स्वतंत्रता अंश (df) = (4-1) (2-1) = 3

स्वतंत्रता अंश एवं सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणी मान = 07.815

x^2 44-496 > 07-815

तालिका क्रमांक 1.1 में पानी टंकी निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 44.496 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व पेयजल व्यवस्था में पानी टंकी निर्माण कराने में आय के अनुसार अपनी भूमिका प्रदान करता है।

तालिका क्रमांक 1.2

उत्तरदाताओं की शिक्षा का घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण की भूमिका के मध्य सह–संबंध

क्र.	शिक्षा	घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण		योग आवृत्ति (%)
		हाँ (%)	नहीं (%)	
1.	निरक्षर	012 (52.18)	011 (47.82)	23 (07.04)
2.	प्राथमिक	061 (76.25)	019 (23.75)	80 (24.55)
3.	माध्यमिक	081 (90.00)	009 (10.00)	90 (27.61)

4.	हाईस्कूल	047 (85.46)	008 (14.54)	55 (16.87)
5.	हायर सेकेण्डरी	061 (88.40)	008 (11.60)	69 (21.17)
6.	महाविद्यालय	008 (88.89)	001 (11.11)	09 (02.76)
	योग	**270 (82.82)**	**056 (17.18)**	**326 (100)**

काई वर्ग का परिकलित मान x^2 = 22-886

सार्थकता स्तर p = 0-05

स्वतंत्रता अंश (df) = (6-1)(2-1) = 5

स्वतंत्रता अंश एवं सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणी मान = 11.070

x^2 22-886 > 11-070

तालिका क्रमांक 1.2 में घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 22.886 सारणी मान 11.070 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात शिक्षित व्यक्ति ग्राम में घरेलू जल निकासी व्यवस्था पर अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है।

तालिका क्रमांक 2.1

ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति पर उत्तरदाताओं के मत

क्र.	ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अच्छी	015	04.60
2.	सामान्य	115	35.28
3.	खराब	196	60.12
	योग	326	100

तालिका क्रमांक 2.1 की चित्रमय प्रस्तुति

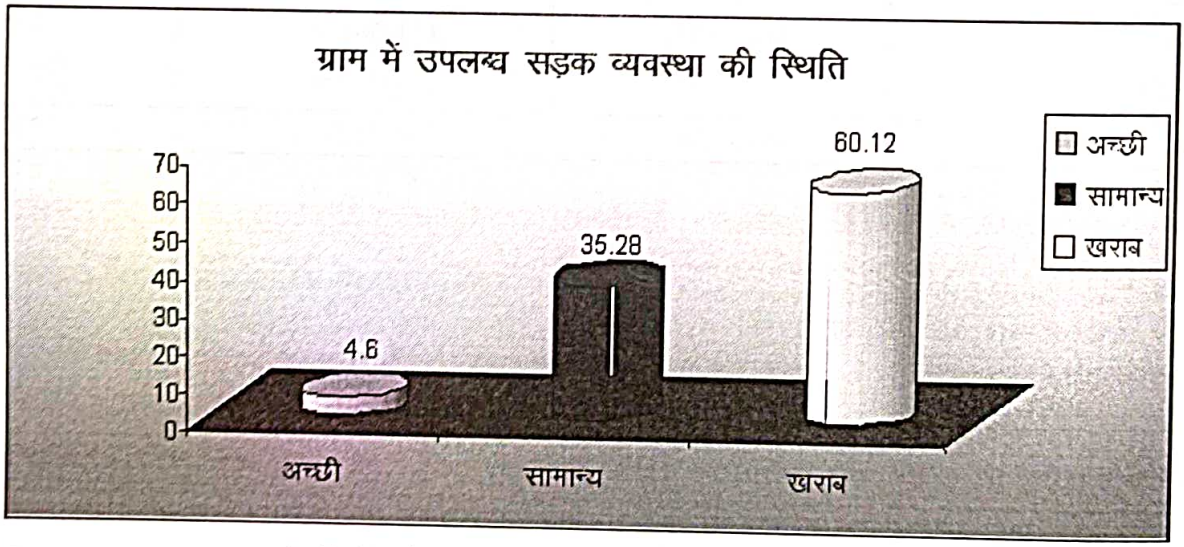

ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है, कि सर्वाधिक 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क व्यवस्था खराब है, तथा 35.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति सामान्य है, एवं 04.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति अच्छी है।

अतः निष्कर्ष निकलता है, कि आज भी ग्राम अच्छी सड़क से वंचित है, जो ग्राम पंचायत की विफलता को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष

पेयजल व्यवस्था के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका से यह ज्ञात हुआ कि, पानी टंकी का निर्माण कराने में 44.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेयजल स्रोत पर उचित दवाई का छिड़काव कराने में 76.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। घरेलू जल के निकासी

हेतु नाली निर्माण कराने में 52.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेयजल व्यवस्था के क्षेत्र के कार्यों पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीणों के प्रतिदिन के आवश्यक कार्यो पर ग्रामीण नेतृत्व का योगदान अपेक्षाकृत सामान्य है, अतः ग्रामीण नेतृत्व में ग्राम विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने की आवश्यकता है।

पानी टंकी निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों से विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 44.496 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व पेयजल व्यवस्था में पानी टंकी निर्माण कराने में आय के अनुसार अपनी भूमिका प्रदान करता है।

घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 22.886 सारणी मान 11.070 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् शिक्षित व्यक्ति ग्राम में घरेलू जल निकासी व्यवस्था पर अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है।

ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क व्यवस्था खराब है तथा 35.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति सामान्य है, एवं 04.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति अच्छी है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि आज भी ग्राम अच्छी सड़क से वंचित है, जो ग्राम पंचायत की विफलता को प्रदर्शित करता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, स्मार्ट कार्ड हेतु शिविर आयोजन कराने में 67.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पुरूष नसबंदी हेतु प्रेरित करने में 21.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराने में 40.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने में 72.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। सार्वजनिक मूत्रालय निर्माण कराने में 68.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

ग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 0.836 सारणी मान 05.991 से कम है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं है, अर्थात् स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में आयु की भूमिका नहीं होती है।

ग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति में प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 01.901 सारणी मान 07.815 से कम हैं, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं होने की पुष्टि करता है, अर्थात् स्वास्थ्य शिविर लगाने की भूमिका को वैवाहिक स्थिति प्रभावित नहीं करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कराने में 54.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। उचित पेयजल की व्यवस्था में 68.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, जिसमें शत् प्रतिशत सरपंच की भूमिका है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करने में 57.36 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। शालेय निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक वितरण का मूल्यांकन के रूप में 61.04 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। योगाभ्यास हेतु शिविर कराने में 43.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

अतः निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करना, उचित पेयजल की व्यवस्था, शालेय निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक वितरण का मूल्यांकन करने में प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका अधिक है, तथा अन्य ग्रामीण नेतृत्व को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकारी स्कूल में संचालित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की निरीक्षण करने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 46.319 सारणी मान 07.815 से बहुत अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध को दर्शाता है, अर्थात सरकारी स्कूल में संचालित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की निरीक्षण करने की भूमिका को ग्रामीण नेतृत्व के जाति प्रभावित करता है।

अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कराने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 07.948 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् युवा वर्ग की तुलना में अधिक आयु वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कराने का प्रयास कम करता है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि युवा वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान करता है।

अध्ययनगत ग्राम पंचायत में काँजी हॉऊस संचालित होने संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 66.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम पंचायत में काँजी हॉऊस संचालित है, तथा 33.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम पंचायत में काँजी हॉऊस संचालित नहीं है।

काँजी हॉऊस संचालित ग्राम पंचायत के उत्तरदाताओं से पशु संबंधित अभिलेखों की व्यवस्था पर संतुष्टि को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 58.26 प्रतिशत उत्तरदाता असंतुष्ट है, एवं 41.95 प्रतिशत उत्तरदाता पशुओं से संबंधित अभिलेखों की व्यवस्था पर संतुष्ट है।

अतः निष्कर्ष निकलता है, कि कम जनसंख्या वाले ग्राम में ग्रामीण कानून अत्यधिक कठोर होता है, इस कारण काँजी हॉऊस संचालित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में काँजी हॉऊस संचालित की जाती है, जिस पर नियंत्रण रखना मुश्किल है, क्योंकि साधन संपन्न ग्रामीणों का ग्रामीण नेतृत्व व अन्य ग्रामीण विरोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है।

पशुधन के क्षेत्र पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, मृत पशुओं के लिए स्थान आवंटन कराने में 24.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। चारागाह हेतु व्यवस्था कराने में 29.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। जिसमें शत् प्रतिशत सरपंच की भूमिका है। पशु टीकाकरण एवं नस्ल सुधार हेतु शिविर लगाने 71.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पशुधन योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान करने में 91.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

पशु टीकाकरण एवं नस्ल सुधार हेतु शिविर लगाने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 02.962 सारणी मान 07.815 से बहुत कम है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध नही दर्शाता है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि पशु टीकाकरण एवं नस्ल सुधार हेतु शिविर लगाने में ग्रामीण नेतृत्व के जाति का कोई प्रभाव नही होता है।

ग्राम पंचायत में जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की व्यवस्था की स्थिति संबंधी अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 57.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी नहीं है, तथा 32.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उक्त अभिलेखों को ग्राम पंचायत ने व्यवस्थित किया है, एवं 10.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत में जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत में जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधी अभिलेखों को व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व ग्राम सचिव का होता है, इस कारण अधिकांश ग्रामीण नेतृत्व को जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधी अभिलेखों की जानकारी नहीं है, जिससे यह भी निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत के बैठक में उक्त अभिलेखों पर चर्चा नहीं की जाती है।

अतः उक्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है, कि सरकार द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में ग्रामीण नेतृत्व का आंशिक सहयोग होता हैं, क्योंकि ग्रामीण नेतृत्व को पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण अपनी आजीविका पूर्ति में अधिक समय व्यतीत करता है। जिसकी पुष्टि उत्तरदाताओं की आय संबंधी विवरण तालिका क्रमांक 2.1 से स्पष्ट है, तथा अधिकांश ग्रामीण नेतृत्व की आर्थिक स्थिति निम्न होती है।

अध्ययनगत क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में ग्रामीण नेतृत्व का सहयोग होने संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 73 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक सहयोग करते हैं, तथा 21.17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पूर्णतः सहयोग है, एवं 05.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का सरकार द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में नहीं के बराबर सहयोग है, अतः उक्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है, कि सरकार द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में ग्रामीण नेतृत्व का आंशिक सहयोग होता है, क्योंकि ग्रामीण नेतृत्व को पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण अपनी आजीविका पूर्ति में अधिक समय व्यतीत करता है, जिसकी पुष्टि उत्तरदाताओं की आय संबंधी विवरण तालिका क्रमांक 2.1 से स्पष्ट है तथा अधिकांश ग्रामीण नेतृत्व की आर्थिक स्थिति निम्न होती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के क्षेत्र पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि, राशन कार्ड हेतु शिविर कराने में 92.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संस्था का निरीक्षण के रूप में 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। संबंधित निगरानी समिति को निरीक्षण के प्रति जागरूक कराने में 35.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीणों को खाद्य मिलता है, और ग्रामीण ही ग्रामीण नेतृत्व का चयन करता है, इस कारण ग्राम पंचायत सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पर नियंत्रण अधिक रखने का प्रयास करती है।

राशन कार्ड हेतु शिविर लगाने की भूमिका को उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 15.214 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् राशन कार्ड हेतु शिविर लगाने की भूमिका को ग्रामीण नेतृत्व की मासिक आय प्रभावित करता है।

राशन कार्ड हेतु शिविर कराने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति में प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 01.901 सारणी मान 07.815 से कम हैं, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं होने की पुष्टि करता है।

राशन कार्ड हेतु शिविर कराने की भूमिका के स्तर को उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 84.729 सारणी मान 11.070 से अधिक है, अर्थात् दोनों में सार्थक सह–संबंध है।

सार्वजनिक विवरण प्रणाली संस्था का निरीक्षण का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 29.518 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् सार्वजनिक विवरण प्रणाली संस्था का निरीक्षण को आयु प्रभावित करता हैं।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका से यह ज्ञात हुआ कि, योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का चयन कराने में 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेंशन योजनाओं पर सामूहिक चर्चा का आयोजन करने में 49.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, जिसमें शत प्रतिशत सरपंच की भूमिका है। दिव्यांगों की सहायता में 32.82 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। सामूहिक विवाह कराने में 88.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। अतिवृद्ध जन के लिए घर पर ही पेंशन उपलब्ध कराने में 89.26 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, अतः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि सामूहिक विवाह हेतु प्रयास, अतिवृद्ध जन के लिए घर पर ही पेंशन उपलब्ध कराने का प्रयास अधिकांश ग्रामीण नेतृत्व करता है, जो ग्रामीण समाज में वृद्ध जन की महत्ता को प्रदर्शित करता है। आज भी दिव्यांगों की सहायता हेतु ग्रामीण नेतृत्व को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान की आवश्यकता है।

दिव्यांगों की सहायता करने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 01.385 सारणी मान 05.991 से कम है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं है, अर्थात् दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना ग्रामीण नेतृत्व की आयु से निर्धारित नही होता है।

दिव्यांगों की सहायता करने संबंधी भूमिका को उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 43.306 सारणी मान 11.070 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् शिक्षित व्यक्ति में दिव्यांगों की सहायता करने की भावना अधिक होता है।

सामूहिक विवाह हेतु प्रयास करने संबंधी भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 33.636 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् सामूहिक विवाह हेतु प्रयास करने संबंधी भूमिका को आयु प्रभावित करता है।

सामूहिक विवाह हेतु प्रयास करने संबंधी भूमिका को उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 20.352 सारणी मान 07.815 से अधिक हैं, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् सामूहिक विवाह हेतु प्रयास करने संबंधी भूमिका को आय प्रभावित करता है।

अध्ययनगत समूह के उत्तरदाताओं के प्रयास से युवा खेल प्रतियोगिता आयोजन होने संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 83.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने युवा खेल प्रतियोगिता के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, जबकि 16.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने युवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन के लिए प्रयास किया है। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत द्वारा युवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं के बराबर होता है, ग्रामीण समाज में युवा खेल का महत्व बहुत कम है, क्योंकि ग्रामीण समाज युवा विकास की अपेक्षा ग्रामीण परम्परा के निर्वहन पर अधिक ध्यान देता है। इस कारण दो तिहाई से अधिक ग्रामीण नेतृत्व युवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन के लिए कोई प्रयास नहीं करता है।

उत्तरदाताओं द्वारा ग्रामीणों के विवादों का समाधान कराने संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 63.20 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीणों के विवाद में समझौता कराता है तथा 36.80 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीणों के विवाद में समझौता नहीं कराता है। ग्रामीणों के विवाद में समझौता कराने वाले उत्तरदाताओं से ग्रामीण विवाद का निपटारा में ग्राम पंचायत का सहयोग लेने संबंधी मत को जानने का प्रयास किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 88.78 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीणों के विवाद में ग्राम पंचायत का सहयोग लेता है, जबकि 11.17 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीणों के विवाद में समझौता कराते हैं। ग्रामीणों के विवाद का निपटारा में ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं लेने वाले उत्तरदाताओं से ग्रामीणों के विवाद का निपटारा करने संबंधी जानकारी को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 60.86 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीणों के विवाद का निपटारा ग्रामीण स्तर पर करते हैं तथा 39.14 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीणो के विवाद का निपटारा पुलिस थाने के माध्यम कराता है।

अध्ययनगत समूह के ग्राम में सार्वजनिक भूमि प्रबंधन की स्थिति में यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 59.82 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सार्वजनिक भूमि प्रबंधन सामान्य, तथा 25.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सार्वजनिक भूमि प्रबंधन की स्थिति खराब है, एवं 14.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सार्वजनिक भूमि प्रबंधन अच्छी है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम समाज सार्वजनिक भूमि का उपयोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए करता है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होने से ग्रामीण एक साथ विरोध करते हैं, इस कारण ग्राम पंचायत सार्वजनिक भूमि प्रबंधन को ग्राम विकास के लिए व्यवस्थित करता है।

ग्राम पंचायत द्वारा कचरा इकट्ठा कराने के लिए स्थान आबंटन की स्थिति संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है, कि 87.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित नहीं की गई है, तथा 12.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित की गई है। कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित ग्राम के उत्तरदाताओं से प्रत्येक वार्ड में कचरा इकट्ठा की व्यवस्था की स्थिति को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 64.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार प्रत्येक वार्ड में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित नहीं की गई है, तथा 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार प्रत्येक वार्ड में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित है, अतः विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण समाज कृषि प्रधान है, जहां प्रत्येक घर गड्ढा खोदकर कचरा इकट्ठा करते है तथा इसका उपयोग खाद के रूप में करता है, परन्तु जिस ग्राम की जनसख्या का घनत्व अधिक होता है, वहाँ ग्राम पंचायत कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित करता है।

अध्ययनगत ग्राम पंचायत की सम्पति की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 62.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सामान्य, तथा 32.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार खराब है, एवं 04.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत की सम्पति की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत की सम्पति सरकारी सम्पति होती है, जिसकी सुरक्षा ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है, और इस प्रावधान का अधिकांश ग्राम पंचायत पालन करती है।

ग्राम पंचायत को बाजार व्यवस्था से प्राप्त होने वाले आय संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 63.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम पंचायत को बाजार व्यवस्था से आय प्राप्त होता है, तथा 36.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम पंचायत को बाजार व्यवस्था से आय प्राप्त नहीं होता है। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि अध्ययनगत क्षेत्र के दो तिहाई से अधिक ग्राम पंचायत को बाजार व्यवस्था से आय प्राप्त होता है, जबकि शेष ग्राम पंचायत में छोटा बाजार होने के कारण आय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंध अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने में 41.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। सिंचाई व्यवस्था कराने में 33.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में 52.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। मृदा परीक्षण हेतु शिविर लगाने में 40.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। उद्यानिकी योजना के प्रति जागरूकता लाने में 46.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 85.482 सारणी मान 07.815 से बहुत अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध को दर्शाता है, अतः कहा जा सकता है, कि विभिन्न जाति वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व में कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की प्रवृत्तियॉ भिन्न भिन्न पायी जाती है।

कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 12.351 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात विभिन्न आयु वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व में कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न पायी जाती है। तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है, कि अधिक आय वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व में कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की भूनिका अधिक है।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, मत्स्य पालन के हितग्राहियों को मदद कराने में 29.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। मत्स्य पालन से ग्राम पंचायत के आय में वृद्धि कराने में 70.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, जिसमें शत् प्रतिशत सरपंच की भूमिका है। मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के लिए शिविर लगाने 26.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

मत्स्य पालन के हितग्राहियों को मदद करने संबंधी भूमिका को उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 16.479 सारणी मान 07.815 से अधिक हैं, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् मत्स्य पालन के हितग्राहियों को मदद करने संबंधी भूमिका को मासिक आय प्रभावित करता है।

मत्स्य पालन से ग्राम पंचायत के आय में वृद्धि करने संबंधी भूमिका को उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 05.048 सारणी मान 11.070 से कम है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं है, अर्थात् मत्स्य पालन से ग्राम पंचायत के आय में वृद्धि करने संबंधी भूमिका को शिक्षा प्रभावित नहीं करता है।

ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, ग्रामीण रोजगार योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान करने में 68.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। प्रतिवर्ष मनरेगा संचालन कराने में 93.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। जिसमें शत प्रतिशत सरपंच की भूमिका है। कुटीर एवं लघु उद्योग हेतु सहायता करने में 58.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं

की भूमिका है। रोजगार स्थल पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में 47.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने में 32.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

रोजगार स्थल पर स्वास्थ्य सुविधा कराने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति में प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 0.947 सारणी मान 07.815 से कम है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं होने की पुष्टि करता है, अर्थात रोजगार स्थल पर स्वास्थ्य सुविधा कराने में वैवाहिक स्थिति का योगदान नहीं होता है।

रोजगार स्थल पर स्वास्थ्य सुविधा कराने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 14.743 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध को दर्शाता है, अर्थात रोजगार स्थल पर सुविधा उपलब्ध कराने की भूमिका जाति से निर्धारित होती है।

विद्युत के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक घर तक विद्युत विस्तार कराने में 68.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, जिसमें तीन चौथाई सरपंच एवं उप सरपंच की भूमिका सकारात्मक है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि प्रत्येक घर तक विद्युत विस्तार कराने की पहल प्रमुख एवं उप प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व अधिक करता है। सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था में 67.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, जिसमें अधिकांश सरपंच की भूमिका सर्वाधिक है। किसानों के लिए विद्युत उपलब्ध कराने में 23.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत के क्षेत्र में प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक है, जो वित्तीय अधिकार होने कारण हो सकता है, अन्य ग्रामीण नेतृत्व का विद्युत के क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कराने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 08.923 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कराने की भूमिका को आयु निर्धारित करती हैं। युवा वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व प्रकाश व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता के साथ महत्व प्रदान करता है।

प्रत्येक घर तक विद्युत विस्तार कराने की भूमिका का विश्लेषण उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति में प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 01.901 सारणी मान 07.815 से कम है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं होने की पुष्टि करता है, अर्थात् प्रत्येक घर तक विद्युत विस्तार करने की भूमिका में ग्रामीण नेतृत्व की वैवाहिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है।

संदर्भ सूची

1. Affolter, F.W., and Findlay, H.J., Assessment of Mobilization and Leadership Challenges in Azerbaijani IDP and Refugee Camps, J. of Convergence, 2002.
2. Abbashahu, Y.B., Schedule Caste Elite : A Study of Elite in Andhra Pradesh, Pragati, Hyderabad, 1978.
3. Agrawal, P.C., and Ashraf, M.S., Equality Privillage : A Study of Special Privillage of Schedule Caste in Hariyana, Shri Ram Centre for Industrial Relation and Human Research, New Delhi, 1977.
4. Agrawal, S.K., Leadership in Industries Setting, Rawat Publication, Jaipur, 1986.
5. Ahalawat, S.R., Rural Local Self Govt. in India, India, Aug. 2013, 49-72.
6. Ahmad, Naser, A Study of Panchayat Finance in India, Published by Centre for Budget and Government Accountability, New Delhi, 1998.
7. Ainapur, L.S., Dynamics of Caste Relations in Rural India, Rawat Publication, Jaipur, 1986.
8. Alagh, Yoginder, K., Panchayatiraj and Planning in India, Participatory Institution and Rural Roads, Asian Institute of Transport Development, New Delhi, 2005.